

# न्यूज़ टुडे

## सहायक प्रजनन तकनीकी नियमन विधेयक (2020) {Assisted Reproductive Technology Regulation (ART) Bill 2020} लोकसभा में प्रस्तुत किया गया

- ART विधेयक को फरवरी, 2020 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया था। इसका उद्देश्य गर्भधारण करने में दम्पत्तियों की सहायता के लिए प्रयोग की जाने वाली निकिता प्रक्रियाओं की नियमानी करना है।
- इस विधेयक का प्रयोजन ART समर्थित कलीनिकों और बैंकों का विनियमन करना, इस प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग को रोकना तथा ART सेवाओं के सुरक्षित एवं नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करना है।
- विधेयक प्रभावित महिलाओं और बच्चों को शोषण से संरक्षण प्रदान कर सकता है, क्योंकि भारत में ART केंद्रों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि परिस्थित हो रही है।
- विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

  - एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जाएगा, जो
    - ❖ एक आचार संघिता निर्धारित करेगा, जिसका अनुपालन इन ऑपरेटिंग कलीनिकों द्वारा किया जाएगा।
    - ❖ भौतिक अवसरण, प्रयोगशाला और नैदानिक उपकरण तथा विशेषज्ञ कार्यबल से संबंधित न्यूनतम मानकों का निर्धारण करेगा।
  - राष्ट्रीय बोर्ड की सहायता हेतु डेटाबेस को बनाए रखने के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और पंजीकरण प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा।
  - राज्य और संघ शासित प्रदेश राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा निर्धारित नैतिकों और योजनाओं के अनुपालन हेतु विशेषतः राज्य बोर्डों और राज्य प्राधिकरणों का गठन करेंगे।
  - इच्छुक दम्पत्तियों की गोपनीयता सुनिश्चित करना और शिशु के अधिकारों की रक्षा करना।

- भारत में लगभग 10-15% विवाहित दंपति बंध्यता (निःसंतान) की समस्या से ग्रसित हैं।
- ART, अत्यधिक तकनीक प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने में असर्वश दम्पत्तियों की सहायता करेगी।

### कृषि पद्धतियों में परिवर्तन और किसानों की आय बढ़ाने के प्रयोजनार्थी तीन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए गए हैं:

- इन विधेयकों का उद्देश्य, कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लिप्त लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए "आत्मनिर्भर भारत अभियान" के तहत जून 2020 में जारी अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करना है।

<b>कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● इसका उद्देश्य किसानों के लिए कृषि उत्पाद बाजार समिति (APMC) के अंतर्गत अधिसंचित बाजार के बाहर भी कृषि विपणन का विस्तार करना और अन्तर्राजीय व्यापार में मौजूद बाधाओं का नियंत्रण करना है।</li> <li>● यह एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का भी प्रस्ताव करता है।</li> </ul>
<b>मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता विधेयक, 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● इसका उद्देश्य अनुबंध कृषि को सुगम बनाना है, जहां एक निजी खरीदार फसली मौसम की शुरुआत में ही एक निश्चित मूल्य पर फसल खरीदने हेतु अनुबंध करता है, जिससे बाजार के अप्रत्याशित होने का जोखिम किसान के बजाय कॉर्पोरेट प्रायोजक की ओर स्थानांतरित हो जाता है।</li> <li>● यह किसानों को प्रसंस्करणकर्ताओं, एग्रीगेटर्स (एकत्रणकर्ता), थोक व्यापारियों, बड़े खुदरा विक्रेताओं और नियार्तकों के साथ समान स्तर पर एवं शोषण के किसी भी भय के बिना जुड़ने के लिए सशक्त बनाएगा।</li> <li>● इससे विपणन लागत में कमी आएगी और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।</li> </ul>
<b>आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 2020</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● इसका उद्देश्य खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू जैसे कृषि उत्पादों को "विनियमन से मुक्त" करना है।</li> <li>● यह खाद्य आपूर्ति शृंखला के आत्मनिकोकरण में सहायता करने के लिए कृषि क्षेत्र में निजी क्षेत्र/विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने तथा व्यापक वित्तव्ययता सुनिश्चित करने में सहयोग करेगा।</li> <li>● यह मूल्य स्थिरता बनाए रखने के दौरान किसानों और उपग्रेडकार्ताओं दोनों की सहायता करेगा।</li> </ul>

### बैंकिंग विनियमन (संशोधन) विधेयक 2020 {Banking Regulation (Amendment) Bill 2020} लोकसभा में प्रस्तुत किया गया

- यह विधेयक, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 में संशोधन करने हेतु प्रस्तुत किए गए बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश 2020 को प्रतिस्थापित करेगा।
  - अध्यादेश द्वारा 1,482 शहरी और 58 बहुराजीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दायरे अंतर्गत लाया गया था ताकि:
    - ❖ उधारदाताओं के पर्यवेक्षण को सुदृढ़ किया जा सके।
    - ❖ जमाकर्ताओं का आत्मविश्वास बढ़ाया जा सके।
    - ❖ पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेट बैंक (PMC) की भाँति होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सके।
    - ❖ महामारी के प्रभाव के कारण होने वाले किसी भी नुकसान से जमाखाता धारकों को सुरक्षा प्रदान की जा सके।
- विधेयक की मुख्य विशेषताएं:
  - यह शहरी सहकारी बैंकों और बहुराजीय सहकारी बैंकों को RBI के प्रत्यक्ष नियमित्य के अंतर्गत लाएगा।
    - ❖ वर्तमान में शहरी और बहुराजीय सहकारी बैंक RBI व रजिस्ट्रार, सहकारी समिति (RCS) के दोहरे विनियमन के अंतर्गत आते हैं।
  - यह विधेयक बैंकों को ऋण स्थगन (moratorium) स्थिति में प्रविष्ट किए बिना RBI को बैंकिंग समस्या को हल करने की अनुमति प्रदान करता है।
    - ❖ इससे पूर्व, RBI को तानावग्रस्त बैंक के लिए एक पुनरुद्धार योजना तैयार करने से पहले उस बैंक को एक ऋण स्थगन (moratorium) अवधि के अंतर्गत रखना होता था।
    - ❖ ऋण स्थगन के दौरान बैंक कोई ऋण नहीं दे सकता है या किसी भी ऋण लिखत (credit instrument) में निवेश नहीं कर सकता है।
  - सहकारी बैंक सहकारिता के आधार पर स्थापित वित्तीय संस्थाएं हैं और ये उनके सदस्यों से संबद्ध होती हैं। इसका तात्पर्य है कि किसी सहकारी बैंक के ग्राहक भी इसके स्वामित्व में भागीदार होते हैं।

### Assisted Reproductive Technology (ART)

- Around 10-15% of married couples in India face infertility.
- ART help couples unable to conceive naturally, with the aid of state-of-the-art technology, to achieve pregnancy.

#### WHO IS IT FOR?

- ART might be an option for women who:
- Cannot conceive naturally
  - Cannot carry pregnancy to term
  - Have genetic disorders
  - Have partners with abnormal sperm

#### TYPES

There are two main types of ART

- Artificial Insemination (AI)
- In vitro fertilization (IVF)



### केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री के अनुसार भारत वर्ष 2023 तक उर्वरक उत्पादन में आत्मनिर्भर हो जाएगा

- वर्तमान में देश का उर्वरक उत्पादन 42-45 मिलियन टन है तथा लगभग 18 मिलियन टन उर्वरकों का आयात किया जाता है।
- मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति हेतु उपयोग किए जाने वाले प्राथमिक उर्वरकों की श्रेणी में नाइट्रोजन-युक्त (युरिया), फॉस्फेट-युक्त (डाई-अमोनियम फॉस्फेट-DAP) और पोटाश-युक्त (म्यूरेट ऑफ पोटाश-MOP) उर्वरक शामिल हैं।
- भारत नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन में दूसरे और फॉस्फेटिक उर्वरकों के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है।
- देश में पोटाश की सीमित भंडार होने के कारण पोटाश की आवश्यकता को आयात के माध्यम से पूर्ण किया जाता है।
- घेरेलू उद्योग द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दे: उत्पादन लागत की तुलना में अल्प मूल्य निर्धारण, सञ्चिडी जारी करने में विलंब आदि।
- उर्वरकों के उत्पादन और कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए चाहए गए कदम:
  - आत्म निर्भर भारत कार्यक्रम के तहत आयात पर नियर्भता को कम करने के लिए 40,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ नई उर्वरक विनियमन इकाइयों को स्थापित किया जा रहा है।
  - उर्वरकों के ताकिक उपयोग हेतु मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना संचालित की गई है।
  - प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से उर्वरक सञ्चिडी का वितरण किया जा रहा है।
  - जैविक और नैनो उर्वरकों का उत्पादन: ये 25 से 30% तक सस्ते उर्वरक हैं और 18 से 35% तक अधिक उपज देते हैं। साथ ही, मृदा का स्वास्थ्य बेहतर बनाए रखने में भी सहायता प्रदान करते हैं।

## संसद द्वारा राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग विधेयक (National Commission for Homoeopathy Bill) और राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग विधेयक (National Commission for Indian System of Medicine Bill) पारित किए गए

- ये विधेयक एक ऐसी चिकित्सा शिक्षा प्रणाली प्रस्तुत करते हैं, जिसका प्रयोजन होम्योपैथिक उपचार के साथ-साथ भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए भी उच्च गुणवत्ता युक्त चिकित्सा पेशेवरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।
- भारत में चिकित्सा की छह प्रमुख पद्धतियां प्रचलित हैं यथा: आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और होम्योपैथी।

राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) विधेयक	राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (NCISM) विधेयक
○ होम्योपैथी की शिक्षा, चिकित्सीय पेशे और चिकित्सा संस्थानों से संबंधित सभी पहलुओं के विनियमन और विकास के लिए 'राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग' का गठन किया जाएगा।	○ भारतीय चिकित्सा पद्धति की शिक्षा, चिकित्सीय पेशे और चिकित्सा संस्थानों से संबंधित सभी पहलुओं के विनियमन और विकास के लिए राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग (NCISM) का गठन किया जाएगा।
○ तीन स्वायत्त बोर्डों का गठन किया जाएगा यथा: <ul style="list-style-type: none"> <li>► होम्योपैथी शिक्षा बोर्ड</li> <li>► चिकित्सीय मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड</li> <li>► नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड</li> </ul>	○ निम्नलिखित स्वायत्त बोर्डों की स्थापना की जाएगी यथा: <ul style="list-style-type: none"> <li>► आयुर्वेद बोर्ड</li> <li>► यूनानी, सिद्ध और सोवा-रिणा बोर्ड</li> <li>► भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए चिकित्सीय मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड</li> <li>► नैतिकता एवं पंजीकरण बोर्ड</li> </ul>
○ होम्योपैथी के लिए प्राथमिक मंच के रूप में एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से राज्य/संघ शासित प्रदेश अपने विचारों और चिंताओं को 'राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग' के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।	○ भारतीय चिकित्सा प्रणाली के लिए प्राथमिक मंच के रूप में एक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से राज्य/संघ शासित प्रदेश अपने विचारों और चिंताओं को 'राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा प्रणाली आयोग' के समक्ष प्रस्तुत कर सकेंगे।
○ होम्योपैथी शिक्षा में स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समरूप राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।	○ स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए समरूप राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
○ इसके अतिरिक्त, चिकित्सक के रूप में फ्रैंकिट्स के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु चिकित्सा संस्थानों से स्नातक करने वाले छात्रों के लिए अतिम वर्ष में एक कॉर्मन नेशनल एक्ज़ाम टेस्ट का आयोजन भी किया जाएगा।	○ इसके अतिरिक्त, जो छात्र शिक्षण को एक पेशे के रूप में अपनाने के इच्छुक हैं, ऐसे स्नातकोत्तर छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी किया जाएगा।

## अन्य सुर्खियाँ

केंद्र ने समान-लिंग विवाह को मान्यता देने की याचिका का विरोध किया है <b>(Centre opposes plea seeking recognition of same-sex marriages)</b>	○ यह याचिका वर्ष 1955 के हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के तहत समान लिंग विवाह को मान्यता प्रदान करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी। ○ केंद्र ने यह उल्लेख करते हुए इसका विरोध किया है कि कानूनी व्यवस्था, समाज और मूल्य समान लिंग वाले युगलों के मध्य विवाह को मान्यता प्रदान नहीं करते हैं। ○ वर्ष 2018 में पांच-न्यायाधीशों की संवैधानिक गीट ने सर्वसम्मति से यह निर्णय दिया था कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के तहत समान लिंग के वयस्कों के मध्य निजी सहमति से संपन्न यौन व्यवहार का अपराधीकरण स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है।
लॉकडाउन के उपरांत 10.4 मिलियन बेरोजगार प्रवासी श्रमिक गृह राज्यों में वापिस लौट गए हैं (10.4 million jobless migrant workers returned home post-lockdown)	○ केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के अनुसार, कुल 10.4 मिलियन प्रवासी श्रमिक कोविड-19 लॉकडाउन के पश्चात नौकरियों के लोप के कारण अपने गृह राज्यों में वापिस लौट गए हैं। ➤ इनमें से लगभग 71% चार राज्यों से थे यथा: उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और राजस्थान। ○ यह भी उल्लेख किया गया है कि कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान उन प्रवासी श्रमिकों का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है, जिनकी नौकरियों की क्षति हुई है अथवा खाद्य व धन के अभाव, प्रवास एवं अन्य कारणों से मृत्यु हुई है।
प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJK)	○ वर्ष 2018 के उपरांत पूर्ववर्ती "बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम" का पुनर्गठन किया गया और इसका नाम परिवर्तित कर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम कर दिया गया। ○ यह कार्यक्रम अल्पसंख्यक समुदायों को विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में बेहतर सामाजिक आर्थिक अवसंरचना सुविधाएँ प्रदान करने के उद्देश्य पर केंद्रित है। ➤ इसके अंतर्गत लगभग 33-40% संसाधन महिला केंद्रित परियोजनाओं के लिए आवंटित किए जाते हैं। ○ प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJK) के तहत राज्य सरकार/राज्य सरकार के निकायों की भूमि तथा सुरक्षा संगठनों, वक्फ व ग्राम पंचायत जैसे अन्य संगठनों की भूमि का विभिन्न शैक्षिक एवं कौशल विकास परियोजनाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है।
एमएएनएके (मिलियन माइंड्स ऑग्मेंटिंग नेशनल एस्प्रेसेशन्स एंड नॉलैज) (MANAK- Million Minds Augmenting National Aspirations and Knowledge)	○ इसे राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान के साथ साझेदारी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वर्ष 2017 में लॉन्च किया गया था। ○ योजना का उद्देश्य विज्ञान और सामाजिक अनुप्रयोगों में निहित एक मिलियन मूल विचारों/नवाचारों को लक्षित करके स्कूली बच्चों के मध्य रचनात्मकता एवं नवोन्नेशी सोच की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ○ मेधावी विचारों को 10,000 रुपये की पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किए जाने के साथ-साथ उनका जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन भी किया जाता है तथा परामर्शी समर्थन भी उपलब्ध कराया जाता है।
राष्ट्रीय स्कूल प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक समग्र उन्नति पहल (निष्ठा/ NISHTH: National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement)	○ यह एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण के माध्यम से विद्यालयी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्षमता निर्माण हेतु एक कार्यक्रम है। ○ इसका उद्देश्य प्रारंभिक स्तर पर सभी शिक्षकों और स्कूल प्रधानाध्यापकों के मध्य दक्षता का निर्माण करना है। ➤ वर्ष 2019-20 में, 16,99,931 स्कूल प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। ○ प्रशिक्षितों (राज्य, जिला, ब्लॉक व क्लस्टर स्तर पर) को अधिगम परिणामों (learning outcomes), विद्यालय आधारित मूल्यांकन, शिक्षार्थी-केंद्रित शिक्षाकास्त्र आदि में प्रशिक्षित किया जाएगा। ○ वर्ष 2020-21 में सेकंडरी (माध्यमिक) स्तर पर निष्ठा (NISHTHA) का द्वितीय चरण आरंभ करने का निर्णय लिया गया है।
टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना (टॉप्स /TOPS: Target Olympic Podium Scheme)	○ TOPS भारत के शीर्ष एथलीटों (खिलाड़ियों) को सहायता प्रदान करने हेतु युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। ○ यह ओलंपिक और पैरालंपिक में भारत के प्रदर्शन में सुधार लाने के उद्देश्य से वर्ष 2014 में आरंभ की गई थी। ○ वर्ष 2018 में TOPS एथलीटों के प्रबंधन और उन्हें पूर्ण समर्थन प्रदान करने के लिए एक तकनीकी सहायता दल का गठन कर इसका पुनरुत्थान किया गया था। ➤ यह टोक्यो-2021, पेरिस-2024 और लॉस-एंजेल्स-2028 ओलंपिक एवं पैरालंपिक खेलों के लिए चयनित संभावित एथलीटों (वर्तमान में 94) को सहयोग प्रदान करती है।

8468022022, 9019066066

www.visionias.in

